भारत में विदेशी निवेश आवश्यकता, परिणाम एवं सुझाव

राजेन्द्र कुमार मीना
व्याख्याता अर्थशास्त्र
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर (राज)

प्रस्तावना -अर्थव्यवस्था के अनेक रूप विद्यमान हैं जिसमें गरीब, अविकसित, पिछड़ी, अर्द्ध विकासित व विकासशील मुख्य हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश कहेंगे।
अर्थव्यवस्था की धुरी वित्त होती हैं जिस प्रकार एक मनुष्य दिल की धड़कनो पर जीवित रहता हैं उसी प्रकार अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए वित्त की आवश्यकता होती हैं।
भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता हैं मानव संसाधन की दृष्टि से भारत दुनियां का सबसे धनी देश कहा जाता हैं लेकिन यही इसकी कमी भी हैं कि इन संसाधनो का सही उपयोग नहीं हो पा रहा हैं और देश आज भी विकसित श्रेणी के राष्ट्र में अपना स्थान नहीं पा सका हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के धीमी गति से विकास होने के मुख्य कारण यहां की प्रति व्यक्ति आय का कम होना हैं प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण जनता में बचत न के बराबर होती हैं और इस कारण से देश में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया धीमी हैं विकसित अर्थव्यवस्था की कुंजी उद्योग धंधे हैं तो उद्योग धंधो का जीवन रक्त पूंजी है इसके अभाव में विकसित राष्ट्र बनने की कल्पना नहीं की जा सकती। देश पूंजी निर्माण की कमी को देखते हुए अप्रैल 1948 में भारत सरकार की औद्योगिक नीति प्रस्ताव में औद्योगिकरण के लिए विदेशी पूंजी की उपयोगिता को स्वीकार किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को गति देने हेतु देश में विदेशी पूंजी का सहारा लेना पड़ा और आज विदेशी पूंजी आवश्यकता बन गई हैं इसका सबूत यह हैं कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी विदेशों में जाकर देश में निवेश हेतु निमंत्रण दे रहे हैं उनके शब्दों में एफ. डी. आय का अर्थ फर्स्ट डेव्लप इंडिया हैं। वही म.प्र. के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2014 तक इन्दौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समीट का आयोजन कर यह साबित कर दिया हैं कि यदि विकास की राह पर अग्रसर होकर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में काबिज होना हैं तो विदेशी निवेश को नकारा नहीं जा सकता।
विकासशील देशों द्वारा अपने देश के आर्थिक विकास हेतु विदेशी पूंजी का सहारा लिया जा सकता हैं इस रूप में प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को आमंत्रित कर विनियोग प्रक्रिया को तीव्र किया जा सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग केवल विदेशी पूंजी ही नहीं लाता हैं, वरन् साथ ही साथ उन देशों की उन्नत तकनीकी भी प्राप्त होती हैं जिससे पूंजी निर्माण में वृद्धि होती हैं। यह समीट विदेशी निवेश के साथ देशी निवेशको को पूंजी लगाकर प्रदेश व देश के विकास में मुख्य भागीदारी बना रहा हैं।

भारत में विदेशी निवेश की आवश्यकता –

1. आधारभूत संरचना के विकास हेतु बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती हैं और देश में बचत कम होने से पूंजी की कमी हैं अतः इस कमी को पूरा करने हेतु विदेशी निवेश आवश्यक हैं।

2. देश में तकनीकी ज्ञान की कमी को पूरा करने के लिए यह आवश्यक हैं कि विदेशी तकनीक को भारत में लाया जाए जब विदेशी निवेश देश में आता हैं तो साथ में तकनीकी ज्ञान भी आता हैं।

3. किसी भी क्षेत्र में पूंजी लगाना जोखिम भरा होता हैं और चुंकी विदेशी पुंजीपति को यह विश्वास होता हैं कि जोखिम उठाकर ही लाभ कमाया

4. जा सकता हैं अत: वह आसानी से निवेश करने को तैयार हो जाता हैं। भारत प्राकृतिक साधनो से परिपूर्ण हैं लेकिन इनका उचित विदोहन न होने का मुख्य कारण पूंजी की कमी हैं अतः प्राकृतिक साधनो के उचित विदोहन हेतु विदेशी निवेश आवश्यक हैं।

5. यदि भारत आर्थिक विकास हेतु विदेशो से ऋण लेकर अपना विकास करता हैं तो इस हेतु इसे बड़ी मात्रा में विदेशी धन ऋण के ब्याज के रूप में चुकाना पड़ेगा इस हिसाब से भी विदेशी निवेश ही महत्वपूर्ण हैं।

6. विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए भारी मात्रा में मशीनों, संयंत्रो, कच्च पदार्थो आदि का आयात करना होता हैं इससे भुगतान शेष प्रायः प्रतिकूल हो जाता हैं यह स्थिति दीर्घकाल तक नहीं रह सकती हैं। विदेशी पूंजी के मिलने पर इस समस्या का अल्पकालीन हल निकल आता हैं।

भारत में विदेशी निवेश के परिणाम - किसी भी कार्य के साथ सकारात्मक **व** नकारात्मक पहलू जुड़े होते हैं विदेशी विनियम जहां एक ओर भारत को विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र बनने में सहायता करेगा वही इसके कुछ विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं।

1. विदेशी निवेश को हम सकारात्मक रूप में देखे तो यहां कृषि, उद्योग, रोजगार, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होकर देश प्रगति की राह पर चल पड़ेगा क्योंकि विदेशी निवेशक पूंजी के साथ तकनीकी ज्ञान, मशीने, पूंजीगत वस्तुएं इत्यादि भी लाता हैं जिसकी हमे नितांत आवश्यकता हैं।

2. नकारात्मक पहलू भारत में विदेशी पूंजी निवेश की भूमिका विशेष गौरव पूर्ण नहीं रही हैं इस देश में सबसे पहले विदेशी पूंजी अंग्रेजी शासन काल में आई थी, जिसक मुख्य उद्देश्य उपनिवेश का शोषण करना था । विदेशी पूंजी ने अनेक क्षेत्रों में भारतीय पूंजी के साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा की । भारतीय को न तो उद्योग संबंधी तकनीको में प्रशिक्षित किया गया और न ही उन्हे प्रबंध व्यवस्था में कोई ऊंचा पद दिया गया था।

विदेशी निवेश से मुख्य हानि यह होती हैं कि लाभ का एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवेशक को देना पड़ता हैं इसके अलावा विदेशी निवेश पर अत्यधिक निर्भरता से घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी हस्तक्षेप का डर रहता हैं।

भारत में विदेशी निवेश हेतु सुझाव - भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कारगर तरीके से सफल बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं –

1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सरलीकृत किया जाना चाहिए ताकि आवश्यक परियोजनाओं को संचालित किया जा सके।

2. निवेश ऐसी परियोजनाओं में आमंत्रित किया जाना चाहिए जिसका मुख्य कार्य वस्तुओं का निर्यात करना हो ताकि लाभ के रूप में विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सके।

3. विदेशी निवेश ऐसी परियोजनाओं में हो जिससे यहां के निवासियों को अधिकाधिक रोजगार प्रदान कर सके।

4. विदेशी निवेश के साथ आये तकनीकी ज्ञान से भारतीयों को ट्रेन किया जाए ताकि आगामी समय में हमे विदेशो पर निर्भर न रहना पड़े ।

5. ऐसी परियोजनाएं जो पर्यावरण को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं नियम स्पष्ट व सख्त होना चाहिए ताकि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ न हो ।

6. कुछ क्षेत्र जो भारत की सुरक्षा व गोपनीयता वाले हैं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रतिबंधित रखना चाहिए।

7. विदेशी पूंजी के कई रूप हैं जैसे रियाती सहायता, गैर-रियाती सहायता व विदेशी निवेश | विदेशी पूंजी के उक्त रूपों में से देश में विदेशी निवेश को प्रौत्साहित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. भारतीय अर्थव्यवस्था - एस. के मिश्र एव बी. के पूरी ।
2. दैनिक भास्कर समाचार पत्र |
3. नई दुनिया समाचार पत्र ।
4. अर्थशास्त्र - एस. एन. नरोलिया, महेश अग्रवाल ।